[2014] 8 एस.सी.आर. 992

संजय गुप्ता और अन्य

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

(रिट याचिका (सिविल) संख्या 338/2006)

31 जुलाई, 2014

[दीपक मिश्रा और वी.गोपाल गौड़ा, जे.जे.]

जांच आयोग अधिनियम, 1952- धाराएँ 8बी और 8सी – गैर-अनुपालन – प्रभाव - अभिनिर्धारित: क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत गठित आयोग ने धारा 8बी और 8सी के प्रावधानों का पालन नहीं किया जिसने अभियुक्त को गंभीर रूप से पूर्वाग्रहित किया, आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को कायम नहीं रखा जा सकता है - नए आयुक्त की नियुक्ति।

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 32 – रिट याचिका - हर्जाना और अन्य राहत की मांग - राज्य के साथ साथ निजी पक्षकारों के खिलाफ – अभियुक्त - एक उपभोक्ता प्रदर्शनी में लगी आग दुर्घटना में 64 मौतों और 100 से अधिक चोटों के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया – अभिनिर्धारित: जांच आयोग अधिनियम के तहत तथ्यान्वेषी आयोग, वैधानिक प्रावधानों के गौर-अनुपालन के लिए टिकाऊ नहीं था - नया आयुक्त नियुक्त किया गया

और उसे रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया- जब तक आयोग का इंतजार है, तब तक हर्जाने का भुगतान करने का दायित्व पक्षकारों पर नहीं लगाया जा सकता है – मामले के तथ्य दर्शाते हैं कि राज्य अधिकारीयों द्वारा वैधानिक उल्लंघन और लापरवाही की गई है – इसलिए, एक अंतरिम उपाय के रूप में, राज्य को पीड़ितों को हर्जाना के रूप में पहले से भुगतान की गई राशी के आलावा कुछ और राशी का भुगतान करने का निर्देश दिया - कार्यक्रम के आरोपी-आयोजकों को न्यायालय में 30 लाख रुपये की राशि जमा करने का भी निर्देश दिया गया, जिसे ब्याज वाले सावधि जमा खाते में रखा जाएगा - विभिन्न दोषी पक्षों के बीच दायित्व के विभाजन पर भी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद निर्णय लिया जाएगा- जांच आयोग अधिनियम, 1950 – क्षति।

आयोजकों (प्रत्यर्थी सं. 10 से 12) द्वारा आयोजित एक उपभोक्ता प्रदर्शनी में आग लगने से 64 लोगों की मौत हो गई और सौ से अधिक लोग घायल हो गए। आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ए, 337, 338 और 427 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। त्रासदी की भयावहता को देखते हुए, राज्य सरकार ने जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत एक सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत वर्तमान रिट याचिका भी दायर की। जिसमे अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्यर्थियों के खिलाफ

संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से पीड़ितों को हर्जाना देने की मांग की गई।

प्रत्यर्थी सं. 10 से 12 (प्रदर्शनी के आयोजकों) ने तर्क दिया कि आयोग द्वारा अधिनियम की धारा 8 बी और 8 सी के अनुपालना नहीं करने के कारण वे गंभीर रूप से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं।

कुछ निर्देश जारी करते हुए और अंतरिम राहत प्रदान करते हुए, न्यायालय ने-

अभिनिर्धारित किया: 1.1. जांच आयोग द्वारा प्रत्यर्थियों को उपस्थित होने के लिए आवश्यक नोटिस की प्रकृति में नोटिस भेजे गए थे। उन्हें अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत नोटिस के रूप में समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, आयोग द्वारा जांच किए गए गवाहों की सूची की जांच करने पर, यह पाया गया कि 10 से 12 प्रत्यर्थियों को लगभग 45 गवाहों की जांच के बाद बुलाया गया था और प्रत्यर्थी-आयोजकों को जिरह का अवसर नहीं दिया गया था। आयोग ने साक्ष्यों के आधार पर और वैधानिक प्रावधानों के कुछ उल्लंघनों का सहारा लेते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इसलिए, रिपोर्ट को कायम रखना मुश्किल है। [पैरा 8] [1003-एच; 1004-ए-बी]

बिहार राज्य बनाम लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य 2003(3) पूरक एससीआर 844 (2003) 8 एससीसी 361-पर निर्भरता।

1.2. स्थिति की गंभीरता और त्रासदी की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, न्यायमूर्ति एस.बी.सिन्हा, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश, को एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त किया गया है। जिन गवाहों की पूर्व आयोग द्वारा जांच की गई और प्रत्यर्थी 10 से 12 द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गई, उनके बयानों को मुख्य परीक्षा के रूप में माना जाएगा और उन्हें प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। यह भी स्वीकार किया गया है कि जिन दस्तावेजों को प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है, जब तक कि उनके ऊपर एक छिद्रान्वेषण न हो, उन्हें प्रदर्शित दस्तावेजों के रूप में माना जाएगा। जिन ठेकेदारों को आयोजकों द्वारा नियुक्त किया गया था, उन्हें पिछले आयोग द्वारा बुलाया गया था, उन्हें वर्तमान आयोग द्वारा बुलाया जाना चाहिए। आयोग को ठेकेदारों को नोटिस जारी करना चाहिए ताकि अधिनियम के तहत कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जा सके। उनके पास समान अवसर होगा जो आयोजकों को उपलब्ध कराया गया है। आयोजकों के साथ-साथ ठेकेदारों को भी उनके समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होगी। आयोग मेरठ में साक्ष्य दर्ज करेगा और दिल्ली में दलीलें सुनेगा। [पैरा 10] [1005-सी-जी]

2.1. उपभोक्ता प्रदर्शनी का आयोजन राज्य सरकार से संबंधित स्थान पर किया गया था, पुलिस अधीक्षक के परामर्श से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अनुमति दी गई थी, राज्य सरकार ने यह देखने की

जहमत नहीं उठाई कि कानून के तहत आवश्यक अन्य वैधानिक अधिकारीयों ने "अनापत्ति प्रमाणपत्र" दिया था या नहीं और यह भी कि आयोजकों द्वारा निर्देशों का कितना पालन किया था। राज्य का प्राथमिक दायित्व यह देखना था कि क्या प्रदर्शनी स्थल पर आयोजकों द्वारा की गई तैयारियों में कोई जोखिम है या नहीं और आच्छादित क्षेत्र में आग बुझाने की उचित व्यवस्था है या नहीं। इन परिस्थितियों में, आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में राज्य द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए कुछ प्रारंभिक व्यवस्था होनी चाहिए। [पैरा 22] [1014-ई-जी]

नीलाबती बेहरा (श्रीमती) उर्फ ललिता बेहरा (उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति के माध्यम से) बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य 1993 (2) एससीआर 581=(1993) 2 एससीसी 746; यूनियन कार्बाइड कार्पोरेशन बनाम भारत संघ 1991 (1) पूरक एससीआर 251=(1991) 4 एससीसी 584; अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम चंद्रिमा दास (श्रीमती) और अन्य 2000 (1) एससीआर 480=(2000) 2 एससीसी 465; सुबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य 2006 (2) एससीआर 67=(2006) 3 एससीसी 178; रघुवंश दीवानचंद भसीन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 2011 (11) एससीआर 300=(2012) 9 एससीसी 791; महमूद नय्यर आज़म बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य 2012 (8) एससीआर 651=(2012) 8 एससीसी 1; मनदीप सिंह बनाम एम.पी. राज्य (2012) 1 एससीसी 748- पर निर्भरता।

भारत संघ बनाम प्रभाकरण 2008 (7) एससीआर 673 = (2008) 9 एससीसी 527 संदर्भित।

2.2. जहां तक प्रत्यर्थीगण 10 से 12 का संबंध है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई दायित्व निर्धारित नहीं किया जा सकता है, और निश्चित रूप से इस स्तर पर नहीं। आयोग की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद ही विभाजन के सिद्धांत पर भी विचार किया जा सकता है, लेकिन पीड़ितों और उनके परिवारों को मुसीबत में नहीं छोड़ा जा सकता है। [पैरा 12 और 27] [1006-ई; 1019-बी]

2.3. चूंकि अनुमति देते समय और प्रदर्शनी के दौरान उचित सावधानी नहीं बरतने में राज्य के अधिकारीयों की ओर से वैधानिक उल्लंघन और लापरवाही हुई है, इसलिए न्यायालय राज्य को अंतरिम उपाय के रूप में क्षतिपूर्ति के भुगतान का निर्देश देता है। [पैरा 27] [1019-सी]

2.4. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि कुछ राशि पहले ही दी जा चुकी है अंतरिम उपाय के रूप में यह निर्देश दिया जाता है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को 5 लाख रुपये और दिए जाएँ, गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को प्रत्येक को 2 लाख रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जायेगा और जिन व्यक्तियों को मामूली चोटें आई हैं उन्हें 75,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाए। मृतकों के कानूनी प्रतिनिधियों

को कुछ अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है और घायल व्यक्तियों को कुछ अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है, उनकी पहचान ज्ञात है और, इसलिए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश केवल उचित पहचान के लिए एक संक्षिप्त जांच करेंगे और राशि का वितरण करेंगे। [पैरा 27] [1019-सी-एफ]

2.5. वर्तमान में राज्य सरकार को निर्देश केवल यह देखना है कि पीड़ित लगातार पीड़ा और निराशा की स्थिति में न रहें। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद रिट याचिका की विचारानियता के मुद्दे पर विचार किया जायेगा। लेकिन आयोजकों को इस संबंध में पूरी तरह से अजनबी बने रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आयोजकों ने इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष कुछ राशि जमा करनी चाहिए और उक्त अवलोकन को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थीगण 10 से 12 को दो महीने की अवधि के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष 30 लाख रुपये की राशि जमा करने का निर्देश दिया जाता है। उक्त राशि ब्याज वाले खाते पर एक सावधि जमा में रखी जाएगी। [पैरा 28] [1020-ए-डी]

2.6. यह व्यवस्था बिल्कुल अंतरिम प्रकृति की है और राज्य और प्रत्यर्थी सं.10 से 12 द्वारा उठाए जाने वाले तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है। [पैरा 28] [1020-डी]

दिल्ली नगर निगम बनाम एसोसिएशन ऑफ़ विक्टिम्स ऑफ़ उपहार ट्रेजेडी और अन्य 2011 (16) एससीआर 1=एआईआर 2012 एससी 100;

डीएवी प्रबंध समिति और अन्य बनाम डबवाली अग्नि त्रासदी पीड़ित संघ और अन्य (2013) 10 एससीसी 494 – संदर्भित।

मामला कानून संदर्भः

2003 (3) पूरक एससीआर 844	भरोसा किया गया	पैरा 9
1993 (2) एससीआर 581	भरोसा किया गया	पैरा 13
1983 (3) एससीआर 508	संदर्भित किया	पैरा 13
1991 (1) पूरक एससीआर 251	भरोसा किया गया	पैरा 13
2000 (1) एससीआर 480	भरोसा किया गया	पैरा 15
2006 (2) एससीआर 67	भरोसा किया गया	पैरा 16
2011 (11) एससीआर 300	भरोसा किया गया	पैरा 17
2012 (8) एससीआर 651	भरोसा किया गया	पैरा 18
(2012) 1 एससीसी 748	भरोसा किया गया	पैरा 18
2011 (16) एससीआर 1	भरोसा किया गया	पैरा 23
2008 (7) एससीआर 673	संदर्भित किया	पैरा 25
(2013) 10 एससीसी 494	संदर्भित किया	पैरा 26

सिविल मूल क्षेत्राधिकार: रिट याचिका (सिविल) संख्या 338/2006

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत।

तुषार मेहता, एएसजी, विकास पाहवा, शांति भूषण, गौरव भाटिया, एएजी, बी.बद्रीनाथ, ऋषि मल्होत्रा, प्रेम मल्होत्रा, डॉ.अशोक धमीजा, बी.वी.बी. दास, कमलेंद्र मिश्रा, पी.परमेश्वरन, आर.डी. उपाध्याय, सुनील कुमार जैन, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, विभु तिवारी, अनुव्रत शर्मा, गुन्नम वेंकटेश्वर राव, मनोज के. मिश्रा, रोहित कुमार सिंह, कार्तिक सेठ, उपस्थित पक्षकारों की ओर से।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया-

दीपक मिश्रा, न्यायाधिपति

1. 10 अप्रैल 2006, विक्टोरिया पार्क, मेरठ में मृणाल इवेंट्स एंड एक्सपोज़िशन द्वारा आयोजित इंडिया ब्रांड उपभोक्ता प्रदर्शनी का आखिरी दिन, विक्टोरिया पार्क, मेरठ में आशा, आकांक्षा, खुशी और उत्सव के साथ दिन की शुरुआत देखी गई, लेकिन, जैसा कि दुर्भाग्य (मानव निर्मित) ने किया था, शाम ढलते ही, वह ब्रांड शो क्षेत्र के आच्छादित परिसर के अंदर एक विनाशकारी आग का मूक दर्शक बन गया, जिसने चौंसठ लोगों के जीवन की चिंगारी को बुझा दिया और सैकड़ों से अधिक लोगों को घायल छोड़ दिया; और घड़ी की टिक टिक के साथ, दिन मानवीय आंसुओं की प्रचुर धारा के मूक दर्शक;, कराहते दर्द और रोने का श्रोता बन गया और अंततः मानव इतिहास में खुद को आपदा के काले दिन के रूप में चिह्नित

कर लिया। कुछ लोग, जो भाग्यशाली थे कि वे मौत से बच गए, उन्हें गंभीर चोटें आईं और कुछ को मामूली चोटें आईं। अप्रैल के सबसे क्रूर दिन ने उपभोक्ता प्रदर्शनी के उत्सव के आखिरी दिन को उन लोगों के परिवारों के लिए एक भयावह त्रासदी में बदल दिया, जो जलकर मर गए, वे पीड़ित जो गंभीर चोटों के बावजूद मौत के पंजे का शिकार नहीं हुए, और दूसरे, थोड़े भाग्यशाली थे, जो मानसिक आघात झेलते हुए मामूली चोटों से बच गए थे। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु का नृत्य सर्वोच्च था और चोट के क्रूर दानव ने गंभीर चोटों के साथ-साथ मामूली चोटें भी दीं। आनंद की सभा पूरी तरह से निराशा में बदल गई और इससे पहले कि लोग त्रासदी की गंभीरता को समझ पाते, सब खत्म हो गया, कानूनी प्रतिनिधियों को छोड़कर, जिन्होंने अपने माता-पिता को खो दिया है, या वे माता-पिता जो हमेशा के लिए अपने बच्चों को देखने से वंचित हो गए हैं, या पत्नियां जो एक मिनट के भीतर विधवा हो गई थीं, राज्य सरकार के अधिकारियों को दोषी ठहराती हैं और शाप दे रहीं थी। समकालीन इतिहास इसे "महान मेरठ अग्नि त्रासदी" के रूप में दर्ज करता है।

2. विक्टोरिया पार्क में त्रासदी की परेड के बाद आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ए, 337,338 और 427 के तहत एक प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज की गई थी। राज्य सरकार ने त्रासदी की भयावहता को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना संख्या 2155/पी/Chh.p-3-2006-12(51) पी/2006 दिनांक 2.6.2006 के तहत, न्यायाधिपति ओ.पी.

गर्ग, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश, को जांच आयोग अधिनियम, 1952 (संक्षेप में "अधिनियम") के तहत एक व्यक्ति आयोग के रूप में नियुक्त किया। आयोग को चार मुद्दों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी, अर्थात्ः -

> "1. उन तथ्यों, कारणों का पता लगाना जिनके कारण उपरोक्त दुर्घटना घटित हुई।
>
> 2. स्थिति को नियंत्रण में रखने के तरीके और साधन तय करना।
>
> 3. उपरोक्त घटना के संबंध में दायित्व का निर्धारण एवं उसकी सीमा।
>
> 4. भविष्य में ऐसी घटना घटित न हो इसके लिए अपनाए जाने वाले उपाय।"

3. लगभग जिस समय आयोग की नियुक्ति की गई थी, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई थी -

> "ए. धारा 304 ए/337/338/427 आईपीसी के तहत सिविल लाइंस, मेरठ, यूपी में दर्ज मामले की एफआईआर संख्या 95/2006 की जांच करने के लिए प्रतिवादी नंबर 13, सीबीआई को निर्देश देने के लिए उचित

रिट, आदेश या निर्देश पारित करें और कानून के अनुसार, मामले की जाँच करे, और यह माननीय न्यायालय समय-समय पर जाँच की निगरानी करे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी अपराध का दोषी व्यक्ति कानून के चंगुल से बचने में सक्षम न हो और जांच यथासंभव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से जल्द से जल्द की जाए।

बी. इस परिमाण की त्रासदी से निपटने के दौरान दोषी प्रशासनिक अधिकारियों के क्रूर और लापरवाह व्यवहार के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देते हुए उचित रिट, आदेश या निर्देश पारित करें।

सी. अपनी जान गंवाने वाले सभी पीड़ितों सहित याचिकाकर्ताओं को, जिनके नाम और विवरण अनुबंध पी.6 में दिए गए हैं, 106 करोड़ रुपये (20 लाख रुपये 53 मृतकों के लिए) की राशी के लिए, संयुक्त रूप से और अलग अलग, प्रत्यर्थियों के खिलाफ क्षतिपूर्ति देने के लिए उचित रिट आदेश या निर्देश पारित करें, इस माननीय न्यायालय द्वारा

सभी पीड़ितों के प्रथम डिग्री उत्तराधिकारियों को सामान रूप से या ऐसे तरीके से वितरित करने के निर्देश के साथ, जो उचित और न्यायसंगत माना जा सकता है।

डी. प्रतिवादियों के विरुद्ध संयुक्त रूप से और अलग-अलग रूप से 63 करोड़ रुपये (126 घायलों के लिए 5 लाख रुपये) का मुआवजा उन घायलों को दिया जाए जिनके नाम और पते अनुबंध पी-6 में उल्लिखित हैं, समान रूप से वितरित किए जाएं, या ऐसे ढंग से जो हो सके इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित एवं अनुकूल माना जाये।

ई. पश्चिमी यूपी में केंद्रीकृत दुर्घटना और ट्रॉमा सेवाओं और अन्य संबद्ध सेवाओं को स्थापित करने और बढ़ाने के उद्देश्य से संयुक्त रूप से और अलग-अलग 50 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान करने के लिए प्रत्यर्थियों के खिलाफ दंडात्मक क्षतिपूर्ति का पुरस्कार दें। प्रत्यर्थी संख्या 3, जिला मजिस्ट्रेट को इस उद्देश्य के लिए एक फंड बनाने और इस माननीय न्यायालय को एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत

करने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसके अनुसार उक्त सेवाएं इस माननीय न्यायालय की देखरेख में स्थापित की जाएंगी।

एफ. सेमिनार, प्रदर्शनियों आदि के आयोजन के लिए एक अस्थायी संरचना बनाते समय सभी को दिशा-निर्देशों का पालन करने के लिए, एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किये जाएँ।"

4. रिट याचिका की सुनवाई के दौरान, हमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री विकास पाहवा ने अवगत कराया कि घटना में 64 लोगों की मौत हुई है, 53 की नहीं। उक्त तथ्य राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विवादित नहीं है। जैसे-जैसे सुनवाई आगे बढ़ी, इस न्यायालय ने आयोग की रिपोर्ट के संबंधित हिस्से की अनुवादित प्रति दाखिल करने का निर्देश दिया क्योंकि यह पहले ही सक्षम प्राधिकारी को सौंपी जा चुकी थी। आदेश के अनुपालन में, राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 5.6.2007 की रिपोर्ट को अभिलेख पर लाया है। उक्त रिपोर्ट के अवलोकन पर, हमने पाया कि आयोग ने सभी पहलुओं के संबंध में अपने निष्कर्ष दे दिए हैं।

5. कार्यक्रम के आयोजकों 10 से 12 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने प्रस्तुत किया कि आयोग ने अधिनियम की धारा 8 बी और 8 सी का अनुपालन न करके गंभीर त्रुटि की

है, जिसके परिणामस्वरूप उक्त प्रत्यर्थियों को गंभीर रूप से पूर्वाग्रह हो गया है. यह उनका आगे का प्रस्ताव है कि उन्हें केवल अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत नोटिस जारी किया गया था, लेकिन यह अधिनियम की धारा 8 बी और 8 सी के तहत अनिवार्य आवश्यकताओं को पूरा नहीं करेगा।

6. उक्त प्रस्तुतिकरण की सराहना करने के लिए, अधिनियम की धारा 8, 8 ए, 8 बी और 8 सी का संदर्भ लेना उचित है। धारा 8 में आयोग द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया का प्रावधान है, जो उसे अपनी बैठक के स्थान और समय को तय करने और सार्वजनिक या निजी तौर पर बैठने का निर्णय लेने सहित अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 8 ए में प्रावधान है कि आयोग की रिक्ति या संविधान में बदलाव के कारण जांच बाधित नहीं होगी। धारा 8 बी और 8 सी जिस पर श्री शांति भूषण ने जोर दिया है, को पुन: प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। वे इस प्रकार पढ़ते हैं:-

> "8 बी. जिन व्यक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनकी बात सुनी जाएगी - यदि, जांच के किसी भी स्तर पर, आयोग, -
>
> (i) किसी व्यक्ति के आचरण की जाँच करना आवश्यक समझता है; या

(ii) यदि उसकी राय है कि जांच से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

आयोग उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई का और अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर देगा:

बशर्ते कि इस धारा की कोई भी बात वहां लागू नहीं होगी जहां किसी गवाह की साख पर महाभियोग लगाया जा रहा हो।

8 सी. कानूनी व्यवसायी द्वारा जिरह और प्रतिनिधित्व का अधिकार - उपयुक्त सरकार, धारा 8 बी में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति और, आयोग की अनुमति से, कोई अन्य व्यक्ति जिसका साक्ष्य आयोग द्वारा दर्ज किया गया है, -

(ए) अपने द्वारा प्रस्तुत गवाह के अलावा किसी अन्य गवाह से जिरह कर सकता है;

(बी) आयोग को संबोधित कर सकता है; और

(सी) आयोग के समक्ष किसी कानूनी व्यवसायी द्वारा या आयोग की अनुमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व किया जा सकता है।"

7. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने प्रस्तुत किया है कि प्रत्यर्थी 10 से 12 को गवाहों से जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया

गया, हालांकि वे उक्त जांच और आयोग द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों से सीधे प्रभावित हैं। उनके द्वारा प्रचारित किया गया है कि उक्त प्रत्यर्थियों को जो नोटिस भेजा गया था वह मूल रूप से अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत है। अपने कथन को मजबूत करने के लिए उन्होंने हमारा ध्यान आयोग द्वारा भेजे गए नोटिसों की ओर आकर्षित किया है। हम आयोग द्वारा आयोजकों में से एक, अर्थात्, प्रत्यर्थी संख्या 10, लाखन तमर को भेजे गए नोटिसों में से एक का संदर्भ ले सकते हैं। उक्त नोटिस इस प्रकार है:-

"श्री लाखन तमर, (जेल में),

आयोजक, उपभोक्ता प्रदर्शनी,

विक्टोरिया पार्क,

मेरठ,

माध्यम से

अधीक्षक, जिला जेल, मेरठ,

मेरठ

10 अप्रैल को जनपद मेरठ के थाना सिविल लाइन क्षेत्र के विक्टोरिया पार्क में ब्रांड उपभोक्ता प्रदर्शनी के 3 पंडालों में भीषण आग लगने की दुखद घटना घटी। कारणों, परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को तय करने के लिए,

उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिसूचना संख्या 2155p/Chh.p-3-2006-12(51)पी/2006 दिनांक 2 जून 2006 जारी करते हुए जांच आयोग अधिनियम 1952 (1952 का सरकारी आदेश संख्या 60) के तहत एक सदस्यीय जांच आयोग नियुक्त किया है और उक्त आयोग प्रगति पर है। आयोग निम्नलिखित मुद्दों की जांच कर रहा है:

1. उन परिस्थितियों एवं कारणों का पता लगाना जिनके कारण उपरोक्त दुर्घटना घटित हुई।

2. भविष्य में ऐसी घटनाओं पर नियंत्रण रखने के तरीकों और साधनों की सिफारिश करना।

3. उपरोक्त घटना के संबंध में दायित्व का निर्धारण एवं उसका निर्धारण।

4. भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अपनाए जाने वाले उपाय.

उक्त पूछताछ के लिए आपकी उपस्थिति अनिवार्य रूप से आवश्यक है। आपको 27 सितंबर 2006 को सुबह 10:30 बजे आयोग के समक्ष उपस्थित होने और अपने बयान की रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाता है। आपको आयोग के समक्ष सभी दस्तावेज़, पत्राचार,

अधिनियम, नियम, सरकारी आदेश, प्रस्तुत करना भी आवश्यक है। घटना की परिस्थितियों से संबंधित विभागीय आदेश, यदि कोई हो।

आपको यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त नोटिस जांच आयोग अधिनियम 1952 (सरकारी आदेश संख्या 60 सन् 1952) के प्रावधानों के तहत जारी किया गया है और जिसका अनुपालन आवश्यक, अनिवार्य और बाध्यकारी है।"

8. इसी तरह के नोटिस अन्य आयोजकों को भी भेजे गए थे। उक्त नोटिस के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि उक्त नोटिस उसे उपस्थित होने की आवश्यकता वाले नोटिस की प्रकृति में है। इसे अधिनियम की धारा 4(ए) के तहत एक नोटिस के रूप में समझा जाना चाहिए। इसके अलावा, उन गवाहों की सूची की जांच पर, जिनकी आयोग द्वारा जांच की गई थी, हमने पाया कि प्रत्यर्थी 10 से 12 को लगभग 45 गवाहों की जांच के बाद बुलाया गया था और प्रत्यर्थी-आयोजकों को जिरह का अवसर नहीं दिया गया था। आयोग ने साक्ष्यों के आधार पर और वैधानिक प्रावधानों के कुछ उल्लंघनों का सहारा लेते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

9. बिहार राज्य बनाम लाल कृष्ण आडवाणी और अन्य के मामले में, अधिनियम की धारा 8 बी की व्याख्या करते हुए, जिसे 1971 के संशोधन

अधिनियम 79 द्वारा क़ानून में लाया गया है, न्यायालय ने इस प्रकार राय दी है: -

> "8. गौर करने वाली बात यह है कि यह संशोधन मुख्य अधिनियम के पारित होने के लगभग 20 साल बाद लाया गया था। पिछले दो दशकों के अनुभव ने विधायिका को यह एहसास कराया होगा कि जांच के दौरान ऐसे व्यक्ति पर ध्यान देना आवश्यक होगा जिसके आचरण की जांच करना आयोग आवश्यक समझता है या जिसकी प्रतिष्ठा पर जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आगे यह भी प्रदान किया गया है कि ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का और अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर मिलेगा। इस प्रकार प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को वैधानिक प्रावधान के रूप में शामिल किया गया। इस प्रकार यह आयोग का दायित्व है कि वह किसी व्यक्ति को कोई भी टिप्पणी करने या राय व्यक्त करने से पहले एक अवसर दे, जिससे उस व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना न हो। इस बात पर ज़ोर देने की ज़रूरत नहीं है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफलता कार्रवाई के साथ-साथ उसके परिणामों को भी रद्द कर देती है।"

10. कानून के उपरोक्त उच्चारण को देखते हुए, रिपोर्ट को बनाए रखना मुश्किल है। हम यहाँ यह कहने के लिए बाध्य हैं कि सुनवाई के दौरान, हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता से पूछा था कि यदि आयोग की रिपोर्ट को रद्द कर दिया जायेगा तो आयोग को अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए आगे बढ़ना होगा। उक्त स्थिति को स्वीकार कर लिया गया। एक और सुझाव दिए जाने पर, पक्षों के विद्वान अधिवक्ता आयोग के रूप में एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए निष्पक्ष रूप से सहमत थे। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता ने सीलबंद लिफाफों में कुछ नाम सुझाये थे, लेकिन कोई समानता नहीं थी। स्थिति की गंभीरता, त्रासदी के परिमाण को ध्यान में रखते हुए, उचित विचार-विमर्श पर हम न्यायमूर्ति एस.बी. सिन्हा, जो पहले इस न्यायालय के न्यायाधीश थे, को एक सदस्यीय आयोग के रूप में नियुक्त करते हैं। पक्षों के विद्वान अधिवक्ता इस बात पर सहमत है कि गवाह, जिनसे पिछले आयोग द्वारा पूछताछ की गई थी और प्रत्यर्थीगण 10 से 12 द्वारा प्रतिपरीक्षा नहीं की गई थी, उन्हें प्रत्यर्थी द्वारा प्रतिपरीक्षा के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। यह भी स्वीकार किया गया है कि दस्तावेज़ जिन्हें प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया गया है, जब तक कि उनके ऊपर एक कोई केविल न हो, उन्हें प्रदर्श दस्तावेजों के रूप में माना जाएगा। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण ने कहा कि जिन ठेकेदारों को आयोजकों ने नियुक्त किया था, उन्हें न्यायाधीश ओ.पी.गर्ग आयोग द्वारा तलब किया गया था, उन्हें वर्तमान आयोग द्वारा बुलाया जाना चाहिए। उक्त

निवेदन की सराहना करते हुए, हम सोचते हैं कि यह उचित है कि आयोग को ठेकेदारों को नोटिस जारी करना चाहिए ताकि अधिनियम के तहत कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जारी रह सके। कहने की जरूरत नहीं है कि उन्हें वही अवसर मिलेगा जो आयोजकों को उपलब्ध कराया गया है। आयोजकों आयोजकों के साथ-साथ ठेकेदार भी अपनी-अपनी दलीलों के समर्थन में सबूत पेश करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आयोग मेरठ में साक्ष्य दर्ज करेगा और दिल्ली में तर्क सुनेगा। यह कहने के लिए कोई विशेष जोर देने की आवश्यकता नहीं है कि राज्य आयोग को उसके सुचारू कामकाज के लिए अपेक्षित बुनियादी ढाँचा, सचिवीय कर्मचारी प्रदान करेगा और आयोग की फीस का भुगतान करेगा जो आयोग द्वारा तय की जाएगी। आयोग से जनवरी, 2015 के अंत तक रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया गया है।

11. ऐसी राय रखने के बाद, हम उन पीड़ितों की दुर्दशा के प्रति अपनी न्यायिक अंतरात्मा को शांत नहीं कर सकते, जिन्होंने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। याचिकाकर्ताओं में से कुछ स्वयं पीड़ित हैं या मृतकों के निकटतम परिजन और घायल व्यक्ति हैं जिन्हें इस दुर्भाग्यपूर्ण मानव निर्मित त्रासदी के कारण कष्ट सहना पड़ा है। यह स्वीकृत स्थिति है कि 64 मौतें हुई हैं और कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। ऐसे लोग भी हैं जिन्हें साधारण चोटें आई हैं जैसा कि राज्य ने दावा किया है। हमें अवगत कराया गया है कि राज्य सरकार पहले ही उन व्यक्तियों के कानूनी प्रतिनिधियों को

2 लाख रुपये का भुगतान कर चुकी है, जिन्होंने अंतिम सांस ली है, और केंद्र सरकार द्वारा एक लाख रुपये का भुगतान किया गया है। जहां तक गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों का सवाल है, राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये का भुगतान किया गया है और जिन पीड़ितों को साधारण चोटें आई हैं, उन्हें 50,000/- रुपये का भुगतान किया गया है।

12. हम जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वह यह है कि क्या इस न्यायालय को आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर राज्य सरकार को निर्देश दें कि वह उन शोकाकुल और प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजे की राशि का भुगतान करे, जो पिछले आठ वर्षों से इन्तजार कर रहे हैं, या मामले को अंतिम रूप देने तक उन्हें कुछ राशि मिलनी चाहिए। यदि हम विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण की इस दलील पर ध्यान नहीं देते हैं कि जहां तक प्रत्यर्थियों 10 से 12 का सवाल है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कोई दायित्व तय नहीं किया जा सकता है, तो हम अपने कर्तव्य में असफल होंगे, और निश्चित रूप से इस स्तर पर नहीं। जहाँ तक प्रस्तुतिकरण के पहले भाग का संबंध है, हम इस न्यायालय द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसके निस्तारण के लिए खुला रखते हैं। जहां तक दूसरे पहलू का सवाल है, इस प्रकृति के मामले में सार्वजनिक कानून उपचार और राज्य के दायित्व के मुद्दे पर ध्यान देने के बाद हम इस पर विचार करेंगे।

13. नीलाबती बेहरा (श्रीमती) उर्फ ललिता बेहरा (द्वारा उच्चतम न्यायालय विधिक सहायता समिति) बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में, जे.एस. वर्मा, न्यायाधिपति (तत्कालीन न्यायाधिपति) स्वयं को बताते हुए और वेंकटाचल, न्यायाधिपति ने, विभिन्न प्राधिकारियों को उल्लेख करते हुए, इस प्रकार राय दीः -

> "17. इसका तात्पर्य यह है कि मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के लिए 'सार्वजनिक कानून में मुआवजे का दावा', जिसकी सुरक्षा की गारंटी संविधान में दी गई है, ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए एक स्वीकृत उपाय है, और मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक उपाय का सहारा लेकर किए गए सख्त दायित्व पर आधारित ऐसा दावा, मौलिक अधिकार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान के लिए निजी कानून में दिए गए उपाय से अलग और इसके अतिरिक्त है। संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा अनुपयुक्त होने और मौलिक अधिकारों की गारंटी की अवधारणा से अलग होने के कारण, संवैधानिक उपचार में ऐसी रक्षा उपलब्ध होने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। यह वह सिद्धांत है जो संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मौद्रिक मुआवजे के मुआवजे को उचित ठहराता है,

जब राज्य या उसके सेवकों द्वारा अपनी शक्तियों के कथित अभ्यास और प्रवर्तन में किए गए उल्लंघन के लिए निवारण का यही एकमात्र व्यावहारिक तरीका उपलब्ध है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 का सहारा लेकर संविधान के तहत सार्वजनिक कानून में उपचार का सहारा लेकर मौलिक अधिकार का दावा किया जाता है। रुदुल साह बनाम बिहार राज्य मामले में यही संकेत दिया गया था और यह बाद के निर्णयों का आधार है जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मुआवजा दिया गया था।

18. इस विषय पर एक उपयोगी चर्चा जो मुआवजे के पुरस्कार को सक्षम करने वाले मौलिक अधिकार के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व के आधार पर सार्वजनिक कानून में उपचार के बीच अंतर को सामने लाती है, जिसके लिए संप्रभु प्रतिरक्षा की रक्षा अनुपयुक्त है, और निजी कानून उपाय, जिसमें प्रतिवर्ती है अपकृत्य में राज्य का दायित्व उत्पन्न हो सकता है, यह रतनलाल और धीरजलाल के लॉ ऑफ़ टॉर्ट्स, 22 वें संस्करण, 1992 में न्यायमूर्ति जी.पी. सिंह द्वारा, प्रष्ट 44 से 48 में पाया जाता है।

इसके बाद, विद्वान न्यायाधीश ने यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन बनाम भारत संघ में द्रष्टान्त को संदर्भित करते हुए, कहा: -

"हम सम्मानपूर्वक इस दृष्टिकोण से सहमत हैं कि न्यायालय असहाय नहीं है और अनुच्छेद 32 द्वारा इस न्यायालय को व्यापक शक्तियाँ दी गई हैं जो स्वयं एक मौलिक अधिकार है, इस न्यायालय पर ऐसे नए उपकरण का निर्माण करने का संवैधानिक दायित्व डालता है, जो पूर्ण न्याय करने और संविधान में गारंटीकृत मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं, उचित मामलों में मौद्रिक मुआवजा देने में सक्षम बनाता है, जहां निवारण का यही एकमात्र तरीका उपलब्ध है। अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय को उपलब्ध शक्ति भी इस सम्बन्ध में एक सक्षम प्रावधान है। विपरीत दृष्टिकोण न केवल न्यायालय को शक्तिहीन और संवैधानिक गारंटी को एक मृग-तृष्णा बना देगा, बल्कि कुछ स्थितियों में, जीवन को समाप्त करने के लिए एक प्रोत्साहन हो सकता है, यदि अत्यधिक उल्लंघन के लिए न्यायालय राज्य के खिलाफ कोई राहत देने के लिए शक्तिहीन है, सिवाय इसके कि परिणामी अपराध के लिए गलत काम

करने वाले को सजा और निजी कानून के तहत सामान्य प्रक्रिया द्वारा नुकसान की वसूली। यदि यह सुनिश्चितता कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना कानून के अनुसार नहीं किया जा सकता है, वास्तविक है, तो प्रत्येक उल्लंघन के मामले में अधिकार का प्रवर्तन भी संवैधानिक योजना में संभव होना चाहिए, निवारण का तरीका वही होगा जो प्रत्येक मामले के तथ्यों में उपयुक्त है। सार्वजनिक कानून में यह उपाय उन वंचितों द्वारा लागू किये जाने पर अधिक आसानी से उपलब्ध होना चाहिए, जिनके पास निजी कानून में अपने अधिकारों के प्रवर्तन के लिए साधन नहीं हैं, भले ही, जहाँ अधिक उपयुक्त हो, निजी कानूनी उपायों की हेराफेरी से बचने के लिए इसका उपयोग न्यायिक संयम द्वारा संयमित किया जाना हो।“

डॉ. आनंद, न्यायाधिपति (तत्समय न्यायाधीश) ने अपनी अपरिवर्तनीय राय में कहा हैः -

"34. सार्वजनिक कानून की कार्यवाही निजी कानून की कार्यवाही की तुलना में एक अलग उद्देश्य की पूर्ति करती है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत अपरिहार्य अधिकार के स्थापित उल्लंघन के लिए, इस न्यायालय द्वारा

अनुच्छेद 32 के तहत या उच्च न्यायालयों द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही में, अनुकरणीय क्षति के रूप में मौद्रिक मुआवजे की राहत सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय है और यह नागरिक के गारंटीकृत बुनियादी और अपरिहार्य अधिकारों के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व पर आधारित है। सार्वजनिक कानून का उद्देश्य केवल न केवल सार्वजनिक शक्ति को सभ्य बनाना है बल्कि नागरिकों को यह भी आश्वस्त करना भी है कि वे एक ऐसी कानूनी प्रणाली के तहत रहते हैं जिसका उद्देश्य उनके हितों की रक्षा करना और उनके अधिकारों को संरक्षित करना है। इसलिए, जब न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन या संरक्षण की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 32 या 226 he तहत कार्यवाही में "मुआवजा" देकर राहत देती है, तो यह सार्वजनिक कानून के तहत गलत काम करने वाले को दंडित करने और राज्य पर सार्वजनिक गलती के लिए दायित्व तय करने के माध्यम से ऐसा करता है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के अपने सार्वजनिक कर्तव्य में विफल रहा है। ऐसे मामलों में मुआवजे का भुगतान समझने के लिए नहीं किया जाता है, जैसा कि इसे आम तौर पर निजी कानून के तहत नुकसान

के लिए एक नागरिक कार्यवाही में समझा जाता है, लेकिन व्यापक अर्थ में, नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने, सार्वजनिक कर्त्तव्य के उल्लंघन के कारण हुई गलती के लिए सार्वजनिक कानून के तहत 'मौद्रिक संशोधन' करने के आदेश द्वारा राहत प्रदान करना है। यह मुआवजा अपने सार्वजनिक कानून कर्तव्य के उल्लंघन के लिए गलत काम करने वाले के खिलाफ दिए गए 'अनुकरणीय हर्जाने' की प्रकृति में है और पीड़ित पक्ष को अपकृत्य पर आधारित कार्रवाई में निजी कानून के तहत मुआवजे का दावा करने, सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत में दायर मुकदमे के माध्यम से या/और दंडात्मक कानून के तहत अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए उपलब्ध अधिकारों से स्वतंत्र है।"

15. अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड और अन्य बनाम चंद्रिमा दास (श्रीमती) और अन्य में, इस न्यायालय ने पहले के निर्णयों का हवाला देते हुए रेलवे द्वारा हर्जाना देने से संबंधित उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका से उत्पन्न अपील पर सुनवाई करते हुए इस प्रकार अभिनिर्धारित किया: -

"रेलवे का संचालन एक व्यावसायिक गतिविधि है। यात्रियों को शुल्क के भुगतान पर ठहरने और बैठने की सुविधा

प्रदान करने के लिए विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री निवास की स्थापना करना भारत संघ की वाणिज्यिक गतिविधि का एक हिस्सा है और इस गतिविधि की संप्रभु शक्ति के प्रयोग के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। भारतीय संघ के कर्मचारी जो रेलवे को चलाने और रेलवे स्टेशनों और यात्री निवास सहित प्रतिष्ठानों का प्रबंधन करने के लिए नियुक्त किया जाता है, वे सरकारी तंत्र के आवश्यक घटक हैं जो वाणिज्यिक गतिविधि चलाते हैं। यदि ऐसे कर्मचारियों में से कोई भी अपकृत्य का कार्य करता है, तो केंद्र सरकार, जिसके वे कर्मचारी हैं, अन्य कानूनी आवश्यकताओं के पूरा करने के अधीन, उन कर्मचारियों द्वारा अन्यायपूर्ण व्यक्ति को नुकसान पहुँचाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।“

16. सुबे सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में, सार्वजनिक विधि उपचार में मुआवजे के अनुदान के मामले में, न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दियाः

"इस प्रकार अब यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि राज्य के खिलाफ मुआवजे देना एक लोक सेवक द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के स्थापित

उल्लंघन के निवारण के लिए एक उचित और प्रभावी उपाय है। हालाँकि, मुआवजे की मात्रा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। इस तरह के मुआवजे का पुरस्कार (सार्वजनिक कानून उपचार के माध्यम से) पीड़ित व्यक्ति को सिविल न्यायालय में अतिरिक्त मुआवजे का दावा करने, यातना में निजी कानून उपाय लागू करने में बाधा नहीं बनेगा, और न ही दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 के तहत मुआवजे का आदेश देने वाली आपराधिक न्यायालय के रास्ते में आते हैं।"

17. रघुवंश दीवानचंद भसीन बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में, न्यायालय ने इस विचार को दोहराया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत याचिकाकर्ताओं के सम्बन्ध में मौद्रिक मुआवजा देने की इस न्यायालय और उच्च न्यायालयों की शक्ति और अधिकार क्षेत्र और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन अच्छी तरह से स्थापित हैं।

18. महमूद नय्यर आज़म बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य में, याचिकाकर्ता की मानसिक यातना से निपटने के दौरान – अभिरक्षा में एक आयुर्वेदिक डॉक्टर, इस न्यायालय ने हरदीप सिंह बनाम एम पी राज्य के

मामले के साथ पूर्ववर्ती निर्णयों को संदर्भित करते हुए इस प्रकार निर्णय दिया:

> "35. हमने इन पेराग्राफों को यह समझने के लिए संदर्भित किया है कि कैसे समय के प्रवाह के साथ, मानव गरिमा की आवश्यक अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मानसिक यातना की अवधारणा को दुनिया भर में समझा गया है।
>
> 36. उपरोक्त चर्चा से, इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभिरक्षा में रहने के दौरान किसी भी अभियुक्त के साथ ऐसा कोई व्यवहार किया जाता है जिससे अपमान और मानसिक आघात होता है, मानवीय गरिमा की अवधारणा को नष्ट कर देता है। कानून की महिमा कानून द्वारा शासित समाज में एक नागरिक की गरिमा की रक्षा करती है। यह नहीं भुलाया जा सकता है कि कल्याणकारी राज्य कानून के शासन द्वारा शासित होता है, जिसमे सर्वोच्चता होती है । एडवर्ड बिगॉन ने कहा है, "किसी राष्ट्र के कानून उसके इतिहास का सबसे शिक्षाप्रद हिस्सा होते हैं"। देश के जैविक कानून के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत किसी व्यक्ति के

अधिकारों के बारे में न्यायालय के विभिन्न निर्णयों में एक जीवित जीव के तरह खुद को कई गुना प्रकट किया है। जब कभी-कभी सिटी हॉल के सदस्यों द्वारा नागरिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है और उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है, तो एक पलटवार होना ही चाहिए और जब पलटाव होता है, संविधान का अनुच्छेद 21 एक संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यही कारण है कि अपराध के एक अन्वेषक के पास धैर्य और दृढ़ता के गुण होना आवश्यक है। जैसा कि नंदिनी सत्पथी बनाम पी. एल. दानी में कहा गया है।"

इसके बाद रघुवंश दीवानचंद भसीन (सुप्रा), सूबे सिंह (सुप्रा) और हरदीप सिंह (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए, न्यायालय ने मुआवजे के रूप में 5,00,000/- रुपये (केवल पांच लाख रुपये) की राशि प्रदान की।

19. मुआवजे के अनुदान के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सार्वजनिक कानून उपचार से संबंधित कानूनी स्थिति के बारे में बताते हुए, हम राज्य की जिम्मेदारी और भागीदारी के संबंध में संबोधित करने के लिए बाध्य हैं। याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित श्री विकास पाहवा, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आयोजकों ने उपभोक्ता प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, मेरठ शहर से

दिनांक 27.3.2006 के पत्र के माध्यम से अनुमति मांगी थी और उक्त पत्र में उन्होंने सभी दिशानिर्देशों और सभी सुझाये गए सुरक्षा और एहतियाती उपायों का पालन करने का वचन दिया था और उत्तर प्रदेश अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 के तहत सक्षम अधिकारियों से अन्य अनुमतियाँ भी मांगी और राज्य के अधिकारीयों ने उचित सत्यापन के बिना अनुमति दे दी थी और इसलिए, उन्हें आयोग द्वारा रिपोर्ट में निर्धारित मुआवजे की मात्र सहित सभी विवादास्पद मुद्दों पर निष्कर्ष दर्ज करने के बाद आयोजकों और ठेकेदारों से आनुपातिक रूप से इसकी वसूली के अधीन पहले भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

20. श्री गौरव भाटिया, राज्य की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि दायित्व जो अंततः निर्धारित किया जाएगा, उसे राज्य और आयोजकों के बीच विभाजित किया जाना है और इसे प्रतिशत के आधार पर किया जाना है, अर्थात आयोजकों का दायित्व 85 प्रतिशत और राज्य का दायित्व 15 प्रतिशत होना चाहिए और कहा गया है कि इस स्तर पर भी आनुपातिकता का पालन किया जाना चाहिए।

21. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शांति भूषण का कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत आयोजकों पर दायित्व नहीं डाला जा सकता है क्योंकि शिकायत निजी व्यक्तियों के खिलाफ मान्य नहीं है और, किसी भी स्तिथि में, ठेकेदारों के कृत्य के लिए आयोजकों को परोक्ष रूप से उत्तरदायी

नहीं ठहराया जा सकता है। हमने इन प्रस्तुतियों को नोट किया है लेकिन हम इन पहलुओं को प्रेजेंटी में संबोधित करने का इरादा नहीं रखते हैं। जैसा कि कहा गया है, सटीक मात्रा के सम्बन्ध में, आयोजकों के दायित्व, ठेकेदारों के दायित्व के संबंध में और यदि इस न्यायालय द्वारा उत्तरदायी पाया जाता है, तो आयोग की रिपोर्ट के सम्बन्ध में अंतिम निर्णय पर निर्भर करेगा। जैसा कि पहले कहा गया है, हमें यह देखना होगा कि क्या राज्य और उसके अधिकारी प्रथम दृष्टया उन्हें मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाजन का मुद्दा बाद में आएगा। जैसा कि हम अभिलेख पर सामग्री से पाते हैं, आयोजकों द्वारा जारी अनुरोध पत्र के अनुसरण में, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पुलिस अधीक्षक, मेरठ से एक रिपोर्ट प्राप्त की और यह विचार व्यक्त किया कि यदि कार्यक्रम 6.4.2006 से 10.4.2006 तक आयोजित किया गया था तो कोई आपत्ति नहीं थी। यह भी रिकॉर्ड में आया है कि अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त करने के बाद, आयोजकों ने गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, मेरठ के प्राचार्य से अनुरोध किया कि वे बिल्ड-इन-स्टाइल प्रदर्शनी की मेजबानी के लिए जी.आई.सी. खेल मैदान और शौचालय की सुविधा उक्त तिथियों पर प्रदान करें। उक्त पत्र का प्रासंगिक भाग इस प्रकार हैः

> "कई वरिष्ठ अधिकारियों/टेक्नोक्रेट्स, प्रमुख कंपनियों और अच्छी तरह से तैनात पेशेवरों के समर्थन और भागीदारी के साथ, यह कार्यक्रम अधिकतम संभव पेशेवर तरीके से

आयोजित एक विशिष्ट और बहुत सुव्यवस्थित कार्यक्रम होने का आश्वासन दिया गया है। इसके अलावा इसे जानबूझकर ऐसे समय पर निर्धारित किया गया है जब यह नियमित स्कूल कक्षाओं या अन्य गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करता है। उपरोक्त अनुमान के साथ, यह ईमानदारी से अनुरोध किया जाता है कि कृपया हमें उपरोक्त तिथियों पर जीआईसी खेल के मैदान और शौचालय आदि के लिए संबद्ध सेवाओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाए और सामान्य रखरखाव/प्रारंभिक कार्यों आदि के लिए मैदान भी प्रस्तावित कार्यक्रम से 4 दिन पहले उपलब्ध कराया जाए।"

22. राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य ने कुछ प्रतिबंधों के अधीन अनुमति प्रदान की। यह स्पष्ट किया जाए कि उक्त परिसर एक अतिरिक्त था। याचिका में कहा गया है कि हालांकि पंडालों का ठीक से निर्माण नहीं किया गया था, केवल एक प्रवेश और एक निकास द्वार था, यूपी अग्निशमन सेवा अधिनियम, 1944 का उल्लंघन हुआ था, कोई उचित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएँ नहीं थी फिर भी प्रदर्शनी आयोजित करने की अनुमति दी गई थी। तथ्यों के पूरे दावे से कुछ चीजें बेहद स्पष्ट हैं। उपभोक्ता प्रदर्शनी का आयोजन राज्य सरकार से संबंधित स्थान पर किया गया था, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस अधीक्षक के परामर्श से अनुमति दी थी, राज्य सरकार ने यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि

क्या कानून के तहत आवश्यक अन्य वैधानिक अधिकारीयों ने "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रदान किया था या नहीं और यह भी कि आयोजकों ने दिशा निर्देश का कितना अनुपालन किया है। राज्य का प्राथमिक दायित्व यह देखना था कि क्या प्रदर्शनियों के स्थान पर की गई तैयारी आयोजकों ने किसी भी जोखिम को शामिल किया या नहीं और क्या आच्छादित क्षेत्र में आग बुझाने के लिए उचित व्यवस्था थी या नहीं। इन परिस्थितियों में हम यह सोचने के लिए तैयार हैं कि आयोग की रिपोर्ट की प्रतीक्षा में राज्य द्वारा मुआवजे के भुगतान के लिए कुछ प्रारंभिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

23. यदि हम श्री गौरव भाटिया के एक अन्य निवेदन पर ध्यान नहीं देते हैं तो हम अपने कर्तव्य में विफल होंगे, जो दृढ़तापूर्वक आग्रह करेंगे कि दिल्ली नगर निगम बनाम उपहार त्रासदी के पीड़ितों के संघ और अन्य में बताए गए सिद्धांतों के अनुसार, विभाजन के संबंध में नुकसान पर विचार किया जाना चाहिए। उक्त मामले में नगर निगम ने दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इस न्यायालय ने तथ्यात्मक मैट्रिक्स का विश्लेषण किया, विभिन्न पक्षों के तर्कों पर ध्यान दिया और अधिनिर्णय को निम्नानुसार संशोधित कियाः -

> "तथ्यों और परिस्थितियों, सार्वजनिक कानून उपचार मामलों में दिए गए मुआवजे की राशि और निवारक

उपाय प्रदान करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि 20 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के मामले में 10 लाख रुपये और घटना की तारीख के अनुसार जिनकी उम्र 20 वर्ष या उससे कम थी, उनके संबंध में 7.5 लाख रुपये का पुरस्कार उचित होगा। हम घायलों के मामले में एक-एक लाख रुपये के पुरस्कार में दखल डालने का प्रस्ताव नहीं रखते हैं। मुआवजे के रूप में दी गई राशी पर उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार रिट याचिका की तारिख से 9 प्रतिशत प्रति वर्ष दी दर से ब्याज देना होगा, पीड़ितों या पीड़ितों के कानूनी प्रतिनिधियों को, जैसा भी मामला हो, जहाँ भी वे मुआवजे से संतुष्ट नहीं है, वहां उच्च उपचार की मांग करने की स्वतंत्रता है। कोई भी वृद्धि विशेष रूप से लाइसेंसधारी (थिएटर मालिक) द्वारा वहन की जाएगी।“

24. इसके बाद, समापन भाग में न्यायालय ने सिलसिलेवार तरीके से अपना निष्कर्ष दर्ज किया। कुछ निष्कर्ष हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं: -

"(iv) लाइसेंसधारी (सीए नंबर 6748/2004 में अपीलकर्ता) और दिल्ली विद्युत बोर्ड को उपहार अग्नि त्रासदी के पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए संयुक्त रूप से और

अलग-अलग उत्तरदायी ठहराया जाता है। यद्यपि उनका दायित्व संयुक्त और अनेक है, उनके बीच दायित्व लाइसेंसधारी की ओर से 85% और डीवीबी की ओर से 15% होगा।

(v) सीए नंबर 6748/2004 को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है और उच्च न्यायालय के निर्णय को निम्नानुसार संशोधित किया गया है:

(अ) मृत्यु के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाने वाला मुआवजा 18 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये (20 वर्ष से अधिक आयु वालों के मामले में) और 15 लाख रुपये से 7.5 लाख रुपये (20 वर्ष और उससे कम आयु वालों के मामले में) कर दिया गया है। उक्त राशि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को देय है, जिसका निर्धारण रजिस्ट्रार जनरल (या दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश/कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के नामित व्यक्ति) द्वारा एक संक्षिप्त और सारांश जांच द्वारा किया जाएगा।

(ब) 103 घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए एक लाख रुपये के मुआवजे की पुष्टि की जाती है।

(स) उपरोक्त रकम पर रिट याचिका की तारीख से 9% प्रति वर्ष की दर से दिए जाने वाले ब्याज की पुष्टि की जाती है।

(द) यदि किसी मृत पीड़ित के कानूनी प्रतिनिधि दिए गए मुआवजे से संतुष्ट नहीं हैं, तो उन्हें रजिस्ट्रार जनरल, दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दस्तावेजी प्रमाण (उम्र और आय दिखाने के लिए) के साथ मुआवजे के लिए आवेदन दायर करने की अनुमति है। यदि ऐसा कोई आवेदन तीन महीने के भीतर पेश किया जाता है, तो इसे विलम्ब के आधार पर खारिज नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल या उच्च न्यायालय के विद्वान मुख्य न्यायाधीश/कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा नामित उच्च न्यायपालिका के ऐसे अन्य सदस्य उपरोक्त पैरा के अनुसार उन आवेदनों पर निर्णय लेंगे और मामले को दिल्ली उच्च न्यायालय की खंड पीठ के समक्ष उन्हें देय

अंतिम मुआवजे का निर्धारण करने के लिए परिणामी औपचारिक आदेश देने के लिए रखेंगे।"

25. उक्त मामले में, राधाकृष्णन, न्यायाधिपति ने अपनी सहमति में इस न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद, विशेष रूप से नीलबती बेहरा (ऊपर) में उच्चारण और भारत संघ बनाम प्रभाकरण, में, निम्नलिखित रूप में अभिनिर्धारित किया गयाः -

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत जीवन का अधिकार संविधान के तहत सुरक्षित और संरक्षित सबसे पवित्र अधिकार है, जिसका उल्लंघन हमेशा कार्रवाई योग्य है और उस अधिकार के संरक्षण के लिए किसी वैधानिक प्रावधान की आवश्यकता नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 को सभी सार्वजनिक सुरक्षा क़ानूनों में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि सार्वजनिक सुरक्षा कानून का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की रक्षा करना और उसे हुए नुकसान की भरपाई करना है। सार्वजनिक सुरक्षा कानून के तहत काम करने वाले राज्य और उसके अधिकारीयों से अपेक्षित देखभाल का कर्त्तव्य, कंपनी अधिनियम, सहकारी समिति अधिनियम और ऐसे समान कानूनों जैसे कानूनों के तहत काम

करने वाले अधिकारियों से अपेक्षित वैधानिक शक्तियों और पर्यवेक्षण की तुलना में बहुत अधिक है। जब हम सिनेमैटोग्राफ़िक अधिनियम, 1952 और उसके तहत बनाए गए नियमों, दिल्ली भवन विनियम और बिजली कानूनों के विभिन्न प्रावधानों को देखते हैं, तो अधिकारियों पर देखभाल का कर्तव्य अधिक था और देनदारियां सख्त थीं।"

XX XXX XXX

क्षति में कानूनी दायित्व पूरी तरह से निजी कानून की कार्रवाई से बाहर एक उपाय के रूप में मौजूद है जो आम तौर पर समय लेने वाला और महंगा होता है और इसलिए जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो दावेदार शीघ्र उपचार के लिए संवैधानिक न्यायालयों का रुख करना पसंद करते हैं। बेशक, संवैधानिक न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल केवल असाधारण परिस्थितियों में ही करेंगी जब विशेष रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के कारण गंभीर चोट लगी हो। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय प्रत्येक मामले की

परिस्थितियाँ और तथ्यों के आधार पर अपने तरीके लागू कर सकता है।"

26. उक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, श्री भाटिया ने विभाजन के पहलू पर जोर दिया है। हमने डीएवी प्रबंध समिति और अन्य बनाम डबवाली अग्नि त्रासदी पीड़ित संघ और अन्य के निर्णय की भी सराहना की है, जिसमे न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि उच्च न्यायालय ने जांच आयोग द्वारा तय किए गए मुआवजे के प्रतिशत को संशोधित किया था और तथ्यात्मक स्कोर की सराहना करते हुए, निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया था:

"इस न्यायालय के लिए अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी 8 के बीच मुआवजे के दायित्व को विभाजित करना संभव नहीं है, विशेष रूप से जांच आयोग के समक्ष या उच्च न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड पर भौतिक साक्ष्य की अनुपस्थिति में और विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए की कि राजीव मैरिज पैलेस के साझेदारों की आर्थिक क्षमता क्या बताई गई है। ऐसे निष्कर्षों के अभाव में इस न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के फैसले को विफल करना उचित नहीं है, जो कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा प्रस्तुत जांच

आयोग की रिपोर्ट पर आधारित है और आगे प्रतिवादी 8 की ओर से यह कहा गया है कि परिवार के छह सदस्यों में से दो व्यक्ति, केवल कृष्ण और चंदर भान की उक्त समारोह में जलने के कारण मृत्यु हो गई और इसके अलावा वह भूमि जहां राजीव मैरिज पैलेस बनाया गया था। जिला अधिकारियों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है और इसे "शाहिद स्मारक पार्क" में बदल दिया गया है, और राजीव मैरिज पैलेस के साझेदारों के पास कौन सी अन्य संपत्तियां बची हैं और इसका साक्ष्य इस न्यायालय में या उच्च न्यायालय के समक्ष या इन कार्यवाही में सामने नहीं आया है। इस प्रकार, इसके अभाव में इस न्यायालय के लिए मुआवजे की देनदारी को बांटना और उसे अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी तक ही सीमित रखना संभव नहीं है और मुआवजे की देनदारी का 55% अपीलकर्ताओं और प्रतिवादी 8 दोनों को सीमित रखना और अपीकर्ताओं और प्रतिवादी को संयुक्त रूप से और अलग-अलग जिम्मेदार ठहराना।“

27. हमने उपरोक्त द्रष्टान्त को संदर्भित किया है क्योंकि श्री भाटिया ने इस स्तर पर विभाजन के लिए हम पर दबाव डाला है। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही विभाजन के सिद्धान्त पर विचार किया जा सकता है,

लेकिन, एक गर्भवती महिला, पीड़ितों और परिवारों को मुसीबत में नहीं छोड़ा जा सकता। जैसा के हमने पाया है, अनुमति देते समय और प्रदर्शनी के दौरान उचित सावधानी न बरतने में अधिकारीयों की ओर से वैधानिक उल्लंघन और लापरवाही हुई है, हम राज्य द्वारा अंतरिम उपाय के माध्यम से मुआवजे का प्रत्यक्ष भुगतान का निर्देश देना चाहते हैं। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि कुछ राशि पहले ही दी जा चुकी है, हम एक अंतरिम उपाय के रूप में निर्देश देते हैं कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को 5 लाख रुपये और दिए जाएँ और गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को प्रत्येक को 2 लाख रुपये की राशि और मामूली चोटों का सामना करने वाले व्यक्तियों को 75,000/- रुपये की अतिरिक्त राशि का और भुगतान किया जाएगा। उक्त धनराशि दो माह के भीतर जिला न्यायाधीश मेरठ के समक्ष जमा की जाएगी। विद्वान जिला न्यायाधीश एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश को नामित कर सकता है, जो संक्षिप्त जांच करने पर कानूनी प्रतिनिधियों और पीड़ितों को राशि का भुगतान करेगा। ध्यान दे, जैसा कि राज्य द्वारा दावा किया गया है, मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को कुछ अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है और घायल व्यक्तियों को कुछ अनुग्रह राशि का भुगतान किया गया है, उनकी पहचान ज्ञात है और इसलिए, अतिरिक्त जिला न्यायाधीश केवल उचित पहचान के लिए एक संक्षिप्त जांच करेंगे और राशि का वितरण करेंगे। जिलाधीश, मेरठ जल्द से जल्द संक्षिप्त जांच को सुविधाजनक बनाने

के लिए सभी दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे ताकि पीड़ितों को परेशानी न हो और उक्त उद्देश्य के लिए हम जिलाधीश, मेरठ को चार सप्ताह का समय देते हैं। जमा की तारीख से एक महीने के भीतर भुगतान किया जाएगा।

28. हम दायित्व के निर्धारण, परिमाणीकरण और उनके विभाजन के बारे में पूरी तरह से सचेत हैं जैसा कि उपहार त्रासदी और डबवाली अग्नि त्रासदी मामलों में अभिनिर्धारित किया है। वर्तमान में राज्य सरकार को हमारा निर्देश केवल यह देखने के लिए है कि पीड़ित लगातार पीड़ा और निराशा की स्थिति में न रहें। हमने श्री शांति भूषण के निवेदन पर ध्यान दिया है और इससे पहले कहा है कि हम रिपोर्ट जमा करने के बाद रिट याचिका की स्थिरता के मुद्दे पर ध्यान देंगे। कहने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्थिति में विभाजन का मुद्दा खुला रखा गया है। लेकिन आयोजकों को इस संबंध में पूरी तरह से अजनबी नहीं रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। सुनवाई के दौरान हमने पाया कि आयोजकों को इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष निश्चित राशि जमा करना चाहिए और उक्त अवलोकन के लिए हम प्रत्यर्थियों 10 से 12 को निर्देशित करते हैं कि इस न्यायालय की रजिस्ट्री के समक्ष 30 लाख रुपये की राशि दो महीने की अवधि के भीतर जमा कराये। उक्त राशि ब्याज वाले खाते में सावधि जमा में रखी जाएगी। हम दोहराने की कीमत पर दोहराते हैं कि यह व्यवस्था पूरी तरह से अंतरिम प्रकृति की है और राज्य के विद्वान अतिरिक्त

महाधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 10 से 12 के विद्वान वरिष्ठ वकील श्री शांति भूषण द्वारा उठाए जाने वाले तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

29. जैसा कि हमने आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए तारीख यानी 31.1.2015 तय की है, मामले को 11 फरवरी, 2015 को सूचीबद्ध किया जाए। यदि रिपोर्ट पहले प्रस्तुत की गई है, तो रजिस्ट्री मामले को तुरंत न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध करेगी।

मामला स्थगित किया गया।

कल्पना के. त्रिपाठी

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक विनायक कुमार जोशी, अधिवक्ता द्वारा किया गया है ।

<u>अस्वीकरण</u>- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।

*****